



2026:AHC:10673

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 382 वर्ष 2026

अखिलेश कुमार पराशर

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	पुरुषोत्तम मणि त्रिपाठी
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:	सी. एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम मणि त्रिपाठी और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री एस. के. पाल को सुना।
2. श्री एस. के.पाल, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय में यह बयान दिया है कि उनके पास आवश्यक निर्देश उपलब्ध हैं और वे इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं और वह कोई शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और यह रिट याचिका अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही तय की जाए।
3. दोनों पक्षों की सहमति से, इस रिट याचिका का निस्तारण प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।
4. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 01.01.1996 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था। 01.08.2012 को उसे वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया; हालाँकि, प्रत्यर्थी संख्या 4, खंड विकास अधिकारी, बीजावली खंड, जिला अलीगढ़ द्वारा पारित दिनांक



25.08.2025 और 09.09.2025 के आक्षेपित आदेशों के आधार पर, वसूली का निर्देश दिया गया है।

5. आक्षेपित आदेशों को चुनौती देते हुए, यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता, जिसका सीधा सा कारण यह है कि यह आदेश एकतरफ़ा रूप से, रिट याचिकाकर्ता को बिना कोई सूचना दिए और उसकी पीठ पीछे पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उनका यह भी निवेदन है कि यह मामला न तो धोखाधड़ी का है, न ही तथ्यों को छिपाने का और न ही किसी प्रकार के मिथ्या-कथन का।

7. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचना 06.02.2026 तक जारी कर दी जाएगी।

8. मैंने बार की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्कों को सुना है और अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

9. ज़ाहिर है, ज़ाहिर है, प्रत्यर्थी संख्या 4, खंड विकास अधिकारी, बीजावली खंड, ज़िला अलीगढ़, द्वारा दिनांक 25.08.2025 और 09.09.2025 को पारित आदेशों से यह प्रतीत नहीं होता कि रिट याचिकाकर्ता को कोई सूचना दी गयी थी। | **भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ एवं अन्य; (1994)**

6 एससीसी 154 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह तय किया गया था। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 1991 में, 18.12.1970 से पूर्वव्यापी प्रभाव से, 190 रुपये प्रति माह से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से गंभीर वित्तीय परिणामों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में की गई कटौती के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। विभाग द्वारा उसका वेतन घटाए जाने से पहले उसे कोई सूचना भी नहीं दिया गया था, और यह आदेश उसकी पीठ पीछे, कानून में ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित कर दिया गया था। इस प्रकार, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है, और अपीलकर्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिए भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। निष्पक्ष कार्यप्रणाली की यह मांग है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी को गंभीर वित्तीय परिणामों का सामना करना पड़े, संबंधित व्यक्ति को सूचना दिए बिना और मामले में उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित



नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए 25.7.1991 का वह आदेश (जापन), जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से कायम नहीं रखा जा सकता था; और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करके त्रुटि की है। न्यायाधिकरण का आदेश रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश को, तथा साथ ही न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दिए गए दिनांक 25.7.1991 के उस आदेश (जापन) को भी रद्द करते हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।

10. चूंकि आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि रिट याचिकाकर्ता को सूचना दी गयी थी, अतः इस न्यायालय के पास उक्त आदेश को निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

11. तदनुसार, इस रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है:-

(क) प्रत्यर्थी संख्या 4, खंड विकास अधिकारी, बीजावली खंड, जिला अलीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 25.08.2025 और 09.09.2025 के आदेश निरस्त किए जाते हैं।

(ख) मामले को नए आदेश पारित करने हेतु संबंधित प्राधिकारी को वापस भेजा जाए।

12. मामले का जल्द निस्तारण करने के लिए, संबंधित पक्ष को संबंधित प्राधिकारी के सामने रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना होगा जो कि इस मामले का निस्तारण पूरी तेजी से करेंगे। इसके बाद, अधिकारी रिट याचिकाकर्ता को सुनवाई की तारीख तय करके सूचित करेंगे; यदि किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है, तो रिट याचिकाकर्ता उसे एक आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करेगा, और आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर एक नया आदेश पारित किया जाएगा।

13. उपर्युक्त अवलोकन के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

जनवरी 16, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)